निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश

दिनांक 14 मार्च, 2018 को आयोजित एक जनपद–एक उत्पाद योजना की वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़ एवं इलाहाबाद मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त पर कार्यवाही योग्य बिन्दु (Action Point)

- पावरलूम के बुनकरों को बिजली पर सब्सिडी दी जाती है। जबकि शिल्पियों को नहीं दी जाती। यदि उन्हें सब्सिडी दी जायेगी तो उनकी उत्पादन लागत एक चौथाई हो जायेगा।

  (डा0 रजनीकान्त,निदेशक ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी)
- हस्तशिल्पियों को क्रेडिट गारन्टी स्कीम में ऋण उपलब्ध कराया जाय।

  (डा0 रजनीकान्त,निदेशक ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी)
- हैण्डलूम उत्पादों को विदेशों में बहुत पसन्द किया जाता है। विदेशों में लगने वाले मेलों में ओ0डी0ओ0पी0 के तहत स्टाल दिये जाय।

  (श्री सैयद हसन, प्रतिनिधि, पूर्वान्चल निर्यातक संघ वाराणसी)
- गाजीपुर में वालहैगिंग की काती बनारस से लानी पड़ती है। इसकी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए। रंगाई की पुराने पद्वति के स्थान नये पद्वति प्रयोग मे लायी जाय तथा वित्तीय समस्या को भी दूर किया जाय।

  (श्री कैशरजहॉ, हस्तशिल्पी, गाजीपुर)
- मऊ में एक विपणन केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए और एक पावरलूम औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाय। प्रदूषण नियन्त्रण हेतु सरकार की ओर से ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया जाय।

  (श्री मो0 तैयब पालकी, उद्यमी मऊ)
- कारपेट उत्पाद को तैयार करने व निर्यात करने तक कई नियमों की जटिलतायें है जिसे सरल किये जाने की आवश्यकता है।

  (श्री पियूष बरनवाल, मानद सचिव, आल इण्डिया कार्पेट मैन्युफैक्चर्स एसो0 भदोही)
- फतेहपुर में चादर हेतु धागे की सप्लाई लुधियाना से होती है। धागे की उपलब्धता यदि स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जाये तो चादर का उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ सकता है।

  (श्री शिवराज, फतेहपुर)
- आवॅला खरीदनें वाले बिचौलियों से बचाने हेतु मार्केट बनाया जाय

  (श्री विरेन्द्र पाण्डेय, उद्यमी, प्रतापगढ़)
- वाराणसी में एक सिल्क विविंग सेन्टर की स्थापना होनी चाहिए। जैसे पावरलूम सेक्टर को सुविधा मिल रही है वही सुविधायें सिल्क विविंग सेन्टर को भी मिलें। डिजाईनर को बढ़ावा दिया जाय। टेक्नालाजी अपग्रेड करके हर साल नई–नई टेक्नालाजी लाई जाय।

  (डा0 नितेश धवन, सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोंद्योग वाराणसी)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशः–

- भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उ0प्र0 के लोग नहीं लें पा रहें है। जबकि उनकी समस्याओं का समाधान उन योजनाओं में ही है।
- प्रदेश व भारत सरकार की योजनाओं का संकलन कर उसकी एक लाख कापी तैयार की जाय और प्रत्येक जिले में अध्ययन हेतु वितरित की जायें।
- आनलाईन मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कम्पनियों से समझौता कर एक जनपद–एक उत्पाद के तहत चयनित उत्पाद को सीधे ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में शिल्पियों/निर्यातकों का प्रतिभाग 3–4 गुना बढ़ाया जायेगा ताकि करीगरों एवं क्षेत्र को लाभ मिलें। इसके लिए कैलेण्डर शीघ्र तैयार कर लिया जायेगा।